responsibilities. Everywhere, including in the Parliament Building, the Government's goal of increasing female representation in security forces, which currently stands at a mere 4.4 per cent in Central Armed Police Forces, must be supported by sustainable policies. Women at border security positions often face the dilemma of choosing between careers and the well-being of their children. A 2024 study has revealed that out of 209 police stations in Delhi, only two had sanitary pad vending machines and even those two were poorly maintained. We need urgent and comprehensive reforms. Expanding childcare facilities at every major and minor security installation is crucial. Initiatives like the day care centres of the Bengaluru Police should serve as a model nation wise. Moreover, financial support is essential for situations where onsite childcare is not available. The vision of *Nari Shakti* must go beyond mere optics and must be backed by real tangible support for women. The policy-makers must acknowledge that enabling women to thrive in these roles requires systemic changes, investments in infrastructure, improved workplace facilities, flexible policies, financial assistance and recognition of their dual responsibilities. Childcare should be regarded as a fundamental service, not a luxury. सर, जो मां हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है, क्या उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में सहकार्य करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Fauzia Khan: Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Digvijaya Singh (Madhya Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Smt. Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri N.R. Elango (Tamil Nadu), Shri P. P. Suneer (Kerala), Smt. Ranjeet Ranjan (Chhattisgarh), Smt. Phulo Devi Netam, (Chhattisgarh), Ms. Dola Sen (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri Tiruchi Siva (Tamil Nadu).

Shrimati Sulata Deo, "Demand to reinstate the celebration of Panchayat Divas on 5th March of every year."

Demand to reinstate the celebration of Panchayat Diwas on 5th March of every year

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) : जय श्री जगन्नाथ! उपसभापति महोदय, हम लोग ओडिशा में 5 मार्च को पंचायती राज दिवस मनाते थे। यह आज का नहीं है, बल्कि 30 साल पुराना है, जिसको कैबिनेट ने मंजूर किया था। कांग्रेस के समय में भी बीजू पटनायक के बर्थडे को पंचायती राज दिवस के रूप से मनाया जा रहा था। जब हम लोग alliance Government में भी थे, तब भी 9

साल तक यह मनाया जा रहा था। पीछे भी मनाया जा रहा था, मगर इस बार अभी की गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने 5 मार्च को गवर्नमेंट केलेंडर में लाल अक्षर से अंकित किया और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में यह दिया गया है कि इस दिन बीजू पटनायक का जन्मदिन है और छुट्टी है। इसके बाद क्या हुआ है, इसका पता नहीं है। फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। मुझे यह बताते हुए खेद होता है और बुरा भी लगता है। बीजू पटनायक केवल ओडिशा के लीडर नहीं थे। Biju Patnaik is a tall man. Biju Patnaik is a daredevil pilot. बीजू पटनायक फ्रीडम फाइटर थे और उनके सम्मान में जो कुछ भी किया जाए, वह कम है। वे एक ऐसे लीडर थे, जिनकी डेथ के बाद, उनके शरीर पर तीन कंट्रीज़ के फ्लैग्स डाले गए थे। बीजू पटनायक ऐसे महान व्यक्ति थे। मगर कितनी छोटी मानसिकता है कि कैसे बीजू पटनायक के नाम को हटाया जाए - इसीलिए पंचायती राज दिवस को उस दिन मनाना बंद कर दिया गया।

बीजू पटनायक जी एक ऐसे लीडर थे, जिनका मॉडर्न ओडिशा को गढ़ने में बहुत योगदान था, जैसे पारादीप पोर्ट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, राउरकेला हो, OUAT हो, HAL हो, सैनिक स्कूल हो। इस तरह से आप देखिए, तो बीजू पटनायक जी का इतना योगदान था, मगर आज भूल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पंचायती राज दिवस इसलिए मनाते थे, क्योंकि बीजू पटनायक जी ऐसे व्यक्ति थे, जो महात्मा गाँधी जी के ग्राम स्वराज को आगे ले गए थे। महिला कैसे सशक्त हो, इसके लिए भारतवर्ष में सबसे पहले 33 परसेंट रिजर्वेशन बिल बीजू पटनायक जी ने लगवाया था। इसको किसी और ने कभी नहीं लगाया था। इसीलिए हम लोग इसको पंचायती राज दिवस के नाम से celebrate करते थे। आप सरकार की मानसिकता देखिए कि उसने इसको भी बंद कर दिया। केवल यही नहीं, यह बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी हटाने के लिए सोच रही है। हम लोग बीजू पटनायक जी के नाम पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण (BSKY) कार्ड दे रहे थे, इसने उसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया। ऐसी सरकार आई कि यह केवल परिवर्तन ही परिवर्तन कर रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे, तो नाम के बाद यह डेट में भी परिवर्तन कर रही है। अपने आप जो दिए हैं, उनमें भी परिवर्तन कर रही है। हमारे बीजू पटनायक जी एक बात बोलते थे। £" A person cannot grow with a narrow mindset. अगर मन छोटा करे, तो कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, मन बड़ा रखिए, तो जाति बड़ी होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मन बड़ा करके जाति बड़ी कीजिए। आप यह छोटी मानसिकता छोड़िए और नाम चेंज करना छोड़िए, कलर चेंज करना छोड़िए, डेट चेंज करना छोड़िए। जो कैबिनेट निष्पत्ति हुई थी, गवर्नमेंट ने कैसे एक Executive Order लाकर उसको चेंज कर दिया। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. John Brittas

£ English translation of the original speech delivered in Odia.

(Kerala).

Now, Shri Sanjay Seth: 'Demand to Regulate Coaching Institutes of Competitive Examinations Across the Country.'

Demand to regulate Coaching Institutes of Competitive Examinations across the country

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : सर, आज मैं सदन के सामने एक बड़ा गंभीर मुद्दा रखना चाहता हूँ। देश के अंदर सैकड़ों कोचिंग इंस्टिट्यूट्स चल रहे हैं। आपने भी हर शहर में देखा होगा कि सब जगह कोचिंग इंस्टिट्यूट्स हैं, जो विद्यार्थियों को, छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। लेकिन उनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जो केवल कमाई करने का धंधा बन गए हैं। इसी तरह का एक इंस्टिट्यूट FIITJEE था, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर था, लेकिन उसकी अपनी financial management की गड़बड़ी के कारण एक दिन उसने अपने सारे सेंटर्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो छात्र थे, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उन सब को बहुत नुकसान हुआ और बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई। सर, उनके माता-पिता ने उसके अंदर अपना काफी रुपया लगा कर उन सबको वहाँ पर दाखिला दिलाया था, लेकिन FIITJEE के बंद हो जाने की वजह से अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। सोशल मीडिया पर भी FIITJEE के अभिभावकों की वीडियो आ रही है, जिसमें यह दिखाया गया है कि वे सभी लोग सेंटर्स के बाहर खड़े हैं और सेंटर्स पर ताले लगे हुए हैं। वे सब अब तनाव में हैं और उन छात्रों का पूरा साल बर्बाद हो रहा है। अभी कल ही राजस्थान की सरकार ने कोचिंग इंस्टिट्यूट्स के ऊपर अपनी विधानसभा में एक बिल भी पास किया है, जिसमें वह कोचिंग के ऊपर कुछ नियंत्रण बना रही है।

मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि FIITJEE और अन्य कोचिंग संस्थाओं की वित्तीय जाँच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों और अभिभावकों की फीस वापिस मिले; छात्रों की शिक्षा का नुकसान न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रख सकें; कोचिंग संस्थानों के लिए एक regulatory body बनाई जाए, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी भविष्य में न हो। यह केवल एक संस्थान का संकट नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की मेहनत और सपनों के साथ किया गया धोखा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Seth: Shri Mission Ranjan Das (Assam), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Aditya Prasad (Jharkhand) and Shri Deepak Prakash (Jharkhand).

Shri Meda Raghunadha Reddy: 'Demand to Denotify the Existing Kasireddy Nayana Jyothi Kshetram Lands in Andhra Pradesh from Forest Department.'